

समुत्थानशील भारत के लिये स्टार्टअप को पुनर्जीविति करना

यह एडटीरयिल 13/01/2025 को द हंडि बज़िनेस लाइन में प्रकाशित "Startup India has fuelled entrepreneurial spirit" पर आधारित है। यह लेख भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल के परविरतनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है, जो एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप को फनिटेक और हेलथटेक जैसे क्रिएटरों में वैश्वकि अग्रणीयों के रूप में स्थान दिलाता है। इस गति को बनाए रखने के लिये, विनियामक बाधाओं को दूर करना और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना अनविवार्य है।

प्रलिमिस के लिये:

भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल, उद्योग और आंतरकि व्यापार संवरद्धन विभाग, एग्रीटेक स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा, डीप टेक, भारत का MSME क्रिएटर, आयकर अधिनियम-1961, विश्व बैंक, गलोबल टैलेंट इंडेक्स- 2023, ओपन नेटवरक फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम- 2023, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनियोग, कृषि अवसंरचना कोष।

मेन्स के लिये:

भारत की आरथक संवृद्धि में स्टार्टअप की भूमिका, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

वर्ष 2016 में शुरू की गई **भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल** ने देश को वैश्वकि नवाचार शक्ति के रूप में स्थापित किया है, 500 से अधिक इनक्रियूबेशन केंद्रों को बढ़ावा दिया है तथा स्टार्टअप के लिये एक सुदृढ़ इकोसिस्टम तैयार किया है। इस कार्यक्रम ने प्रशासनिक बाधाओं को तोड़ते हुए टार्गेट 2 और 3 शहरों के उद्यमियों को समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाकर नवाचार को लोकतांत्रकि बनाया है। **फनिटेक** से लेकर हेलथटेक तक, भारतीय स्टार्टअप वैश्वकि अग्रणीयों के रूप में उभरे हैं। यद्यपि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अपार संभावनाओं को दरशाता है, फरि भी इस विकास प्रक्षेपकर को बनाए रखने तथा वैश्वकि डिजिटल अरथव्यवस्था में इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लियामिक कार्यदाँचे में आने वाली चुनौतियों से निपटने के साथ ही मज़बूत उद्योग-अकादमिक सहयोग की आवश्यकता है।

भारत की आरथक संवृद्धि में स्टार्टअप्स की क्या भूमिका है?

- रोजगार सृजन: स्टार्टअप रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदानकरता के रूप में उभरे हैं, जो IT, फनिटेक और ई-कॉमर्स जैसे विविध क्रिएटरों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
 - 31 दिसंबर 2023 तक, **उद्योग और आंतरकि व्यापार संवरद्धन विभाग (DPIIT)** ने कुल 1,17,254 स्टार्टअप को मान्यता दी।
 - इन स्टार्टअप्स ने 12.42 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किया है, जो अरथव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।
 - स्टार्टअप लॉजसिटिक्स, मारकेटिंग और विक्रीता प्रबंधन जैसी सहायक सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे समग्र रोजगार पारस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।
- नवाचार और प्रौद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ावा देना: स्टार्टअप तकनीकी नवाचार में सबसे आगे हैं, जो वास्तवकि विश्व की चुनौतियों का समाधान करने के लिये **AI, ब्लॉकचेन और IoT** का लाभ उठाते हैं।
 - उदाहरण के लिये, एथर एनरजी अपने अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटरों के साथ भारत के EV क्रिएटर में क्रांतिला रही है, जबकि रुद्र एयरोस्पेस के ड्रोन कृषितपादकता में बदलाव ला रहे हैं।
 - **भारत का अनुसंधान एवं विकास बुय** कम बना हुआ है, लेकिन स्टार्टअप एग्रीटेक, एडेटेक और हेलथ-टेक जैसे क्रिएटरों में नवाचार करके इस अंतर की पूरतीकर रहे हैं।
- नरियात और वैश्वकि पहुँच को बढ़ावा देना: स्टार्टअप्स ने अपने कारोबार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक विस्तारित करके भारत की नरियात क्षमताओं को बहुत हद तक बढ़ाया है।
 - रेज़रपे और पेटीएम जैसी फनिटेक कंपनियाँ अब वैश्वकि सतर पर भुगतान समाधान नरियात कर रही हैं, जबकि जोहो और फ्रेशवरक्स जैसी SaaS (सॉफ्टवेयर-एज-अ-सर्विस) फर्म अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर प्रभावी बने हुए हैं। वर्ष 2030 तक अकेले भारत के SaaS सेक्टर से 100 बिलियन डॉलर के राजस्व की उम्मीद है, जो वर्ष 2023 में 13 बिलियन डॉलर (**NITI आयोग**) था। यह वैश्वकि उपस्थिति भारत के बरांड मूल्य को बढ़ाती है और विदेशी मुद्रा आय में योगदान देती है, जिससे देश के भुगतान संतुलन को सहारा

मलिता है।

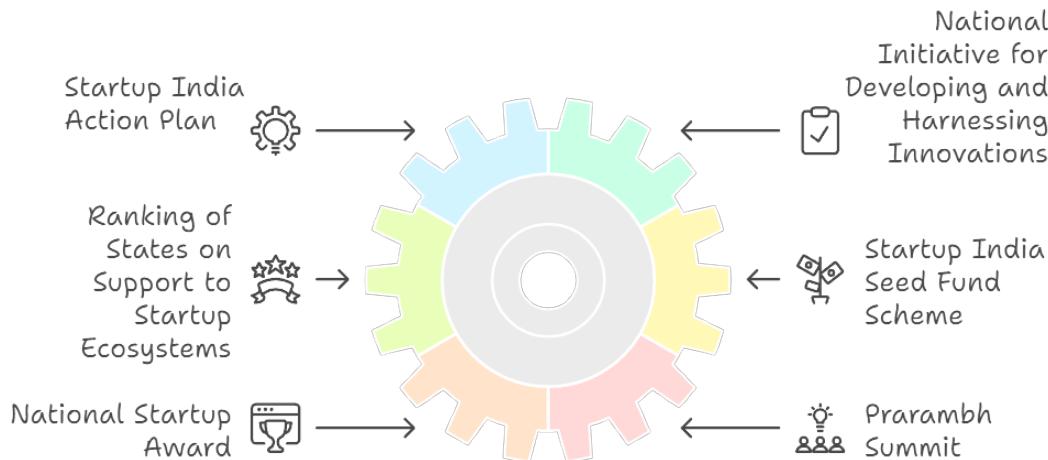
- **वित्तीय समावेशन का समर्थन:** फनिटेक क्षेत्र के स्टार्टअप वंचति आबादी को सस्ती और सुलभ डिजिटिल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके वित्तीय समावेशन का वसितार कर रहे हैं।
 - फोनपे, भारतपे और पेटीएम जैसी कंपनियों ने डिजिटिल भुगतान को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाया है, दसिंबर 2024 में UPI लेन-देन रकिंग रेट 16.73 बिलियन तक पहुँच गया।
 - सूक्ष्म ऋण तथा नियोजिक बैंकिंग के स्टार्टअप MSME और व्यक्तियों को ऋण तक पहुँच प्रदान कर उन्हें सशक्त बना रहे हैं।
 - भारत विशेष के सबसे तेज़ी से बढ़ते फनिटेक बाजारों में से एक है, जिसका वर्तमान आकार 584 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और वर्ष 2025 तक इसके 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो समावेशी आरथिक विकास को बढ़ावा देगा।
- **ग्रामीण अरथव्यवस्था को मज़बूत करना:** स्टार्टअप ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम कर रहे हैं।
 - DeHaat और कर्पॉरेट जैसे एक्राइटिक स्टार्टअप कंपनियों को रयिल टाइम सॉल्यूशन प्रदान कर रहे हैं, जिससे उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हो रही है।
 - आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, तथा अनुमान है कि वर्ष 2025 तक इसका राजस्व 204 बिलियन डॉलर तक पहुँच जायगा।
 - इसके अलावा, विक्रम सोलर जैसे सोलर स्टार्टअप ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, महंगे डीज़िल पंपों पर निभरता कम कर रहे हैं और सतत ग्रामीण आजीविका का समर्थन कर रहे हैं। नवाचार का यह विकिंग रिकरण समान आरथिक विकास को बढ़ावा दे रहा है।
- **महलिं सशक्तीकरण को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप महलिं उद्यमियों को सशक्त बना रहे हैं तथा उन्हें अरथव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान कर रहे हैं।
 - मन्न देशी फाउंडेशन जैसे उद्यम मार्गदर्शन और वित्तपोषण के माध्यम से महलिं-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा दे रहे हैं।
 - आज भारत में 18% स्टार्टअप का नेतृत्व महलिं देने वाले हैं, जो अरथव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
 - IIM बैंगलोर में NSRCEL का महलिं स्टार्टअप कार्यक्रम, कोटक की CSR पहल और स्टार्टअप इंडिया के तहत वित्तीय प्रोत्साहन जैसी पहलें एक अधिक समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण कर रही हैं।
- **हरति एवं सतत विकास को बढ़ावा देना:** नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय क्षेत्र में स्टार्टअप्स जलवायु परवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका नभी रहे हैं।
 - ReNew पावर और इकोज़ेन सॉल्यूशन्स सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण में अग्रणी हैं, जबकि सोरो रीसाइक्लिंग एंड-ऑफ-लाइफ (ELV) वाहनों के पुनर्व्यवस्था पर केंद्रित है।
 - भारत के नवीकरणीय ऊर्जा स्टार्टअप वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य के अनुरूप हैं, तथा हरति ऊर्जा बाज़ार में 15% CAGR (MNRE) की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है।
 - ये स्टार्टअप न केवल आरथिक विकास में योगदान देते हैं बल्कि प्रदायावरण संरक्षण में भी योगदान देते हैं।
- **विदेशी निवेश आकर्षित करना:** भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिये एक आकर्षण का केंद्र बन गया है।
 - वैश्विक निवेशक भारत के विशाल बाज़ार, मज़बूत डिजिटिल बुनियादी अवसंरचना और फलते-फूलते उद्यमशीलता की ओर आकर्षणीय हो रहे हैं।
 - पछिले कुछ वर्षों में रेसिप टेक (R&D-उन्नति) क्षेत्र में लगातार निवेश बढ़ रहा है, जिसकी कुल फंडिंग 6.73 बिलियन डॉलर है।
 - ओला इलेक्ट्रिक और लैंसकारट जैसे स्टार्टअप ने अरबों डॉलर का वित्त पोषण जुटाया है, जिससे आरथिक विकास एवं नवाचार को बढ़ावा मिला है।
- **MSME और सहायक उद्योगों को समर्थन:** स्टार्टअप डिजिटिल उपकरण, ऋण तथा बाज़ार अभियम प्रदान करके MSME के लिये सक्षमकरता के रूप में कार्य करते हैं।
 - भारत का MSME क्षेत्र जो सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान देता है और 150 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार देता है, इन तकनीक-संचालित समाधानों से लाभान्वति हो रहा है।
 - स्टार्टअप्स और MSME के बीच यह तालमेल आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करता है और भारत की अरथव्यवस्था की समग्र प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार कर रहा है।

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिये वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ:** कई प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को सीमित निवेशकों और उद्यम पूँजी की रुचि के कारण प्रारंभिक वित्तपोषण प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है।
 - वर्ष 2023 में, फंडिंग विटिर के परणिमसवरूप लगभग 35,000 भारतीय स्टार्टअप बंद हो गए, जिससे भारतीय स्टार्टअप के लिये फंड जुटाने में लगभग 73% की गिरावट आई।
 - मज़बूत बीज वित्त पोषण तंत्र की अनुपस्थिति और विदेशी निवेशकों पर निभरता के कारण, आरंभिक चरणों में नवाचारों को पोषित करने में अतराल उत्पन्न होता है।
- **विनियोगक और अनुपालन भार:** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सुधारों के बावजूद, स्टार्टअप्स को जटिल विनियोगक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से कराधान और कंपनी पंजीकरण से संबंधित।
 - उदाहरण के लिये, एंजल टैक्स मुद्दे (धारा 56(2)(viib), आयकर अधिनियम-1961) अभी भी विदेशी निवेश के लिये अनशीलिता उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण में बाधा आती है।
 - इसके अतिरिक्त, विशेष बैंक की एक रपिटर में बताया गया है कि भारत में व्यवसाय शुरू करने में औसतन 18 दिन लगते हैं, जबकि OECD उच्च आय वाले देशों में, आमतौर पर केवल 5 प्रक्रयाएँ और 9 दिन लगते हैं, जो अनुपालन प्रक्रयाओं को और भी सरल बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- कुशल प्रतिभा की कमी और प्रतिभा पलायन: स्टार्टअप्स को कुशल प्रतिभा खोज में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वशिष्ठ रूप से AI, ब्लॉकचेन और IoT जैसी उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, जबकि शीरण भारतीय प्रतिभाओं का प्रायः विदेश में पलायन हो जाता है।
 - ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स- 2023 में भारत 103वें स्थान पर है, जो इसे BRICS में सबसे कम वांछनीय देश बनाता है। चीन 40वें स्थान पर समूह में सबसे आगे है, उसके बाद रूस (52), दक्षिण अफ्रीका (68) और ब्राज़िल (69) हैं।
 - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 से अब तक 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है, जिनमें से कई लोग अमेरिकी नवाचार केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं।
 - प्रतिभा का यह अंतर प्रतिभा-प्रधान क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप्स के विकास की गति को बुरी तरह से प्रभावित करता है।
- टयर-2 और टयर-3 शहरों में सीमति बुनियादी अवसंरचना: हालाँकि छोटे शहरों से स्टार्टअप उभर रहे हैं, लेकिन मज़बूत बुनियादी अवसंरचना की कमी— जैसे: हाई-स्पीड इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स और इनक्रियूबेशन सेंटर तक पहुँच उनकी स्केलेबिलिटी को सीमित करती है।
 - उदाहरण के लिये, ग्रामीण भारत में लगभग 50 प्रतिशत लोग गैर-सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिससे डिजिटल-प्रथम स्टार्टअप प्रभावित हो रहे हैं।
 - जबकि डिजिटल इंडिया पहल जैसे कार्यक्रम कनेक्टिविटी में सुधार कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को अभी भी प्रौद्योगिकी और बुनियादी अवसंरचना का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में बहुत-सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- उद्यमता में लैंगिक असमानता: कुछ प्रगतिके बावजूद, सामाजिक बाधाओं, वित्तीय संबंधी पूरवाग्रहों और सीमति मार्गदर्शन अवसरों के कारण भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महलियों का प्रतिनिधित्व कम है।
 - भारत के कुल स्टार्टअप में महलियों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की हसिसेदारी 18% है, लेकिन उन्हें कुल उद्यम पूँजी वित्तीयों का 3% से भी कम प्राप्त होता है।
 - NITI आयोग के अंतर्गत महलि उद्यमता मंच (WEP) जैसी पहलों ने इन अंतरालों को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन महलि उद्यमों को सशक्त बनाने में संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- स्टार्टअप्स की वफिलता दर: नमिनस्तरीय बज़िनेस मॉडल, बाज़ार अनुसंधान की कमी और परचिलन अक्षमताओं के कारण स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा हसिसा पहले पाँच वर्षों के भीतर वफिल हो जाता है।
 - भारत में, लगभग 90% स्टार्टअप प्रायः अपने शुरुआती वर्षों में ही वफिल हो जाते हैं। यह उच्च वफिलता दर मुख्य रूप से अपर्याप्त बाज़ार अनुसंधान, नमिनस्तरीय उत्पाद-बाज़ार फटि, वित्तीय कुप्रबंधन, टीम संघर्ष और एक भरोसेमंद बरांड स्थापित करने में असमर्थता जैसे कारकों के कारण होती है।
 - ज़लिगो (सगिपुर-भारत क्रॉस-बॉर्डर स्टार्टअप) जैसी हाई-प्रोफाइल वफिलताएँ स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेहतर मार्गदर्शन, वित्तीय नियोजन और दीर्घकालिक धारणीयता रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।
- कमज़ोर उद्योग-अकादमिक सहयोग: भारत में अकादमिक और स्टार्टअप के बीच मज़बूत तालमेल का अभाव है, जो नवाचार-संचालित उद्यमता के लिये महत्वपूर्ण है।
 - अमेरिका जैसे देशों के विपरीत, जहाँ स्टैनफोर्ड जैसे संस्थान गूगल जैसे स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय विश्वविद्यालय स्टार्टअप इकोसिस्टम में न्यूनतम योगदान देते हैं, जिससे अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार स्टार्टअप इकोसिस्टम तक अभिगम सीमित हो जाती है।
- सीमति बाज़ार अभिगम और मापनीयता: स्टार्टअप्स को प्रायः घरेलू और वैश्वकि बाज़ारों तक सीमित अभिगम के कारण अपने परचिलन को बढ़ाने में संघर्ष करना पड़ता है।
 - उदाहरण के लिये, DeHaat जैसे कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सीमांत कसिनों को बड़ी आपूरतशृंखलाओं से जोड़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
 - ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे डिजिटल मारकेटप्लेस के लिये सरकार के प्रयासों के बावजूद, स्टार्टअप्स की बाज़ार में अभिगम कम बना हुआ है।
 - यह बाधा नवीन उत्पादों को व्यापक क्रेताओं तक पहुँचने से रोकती है।
- बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा और बाज़ार संतुप्ति: स्टार्टअप इकोसिस्टम, विशेष रूप से ई-कॉमर्स और फनिटेक जैसे क्षेत्रों में, अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी और संतुप्त हो गया है।
 - फ्लिपकार्ट, पेटीएम और अमेज़न जैसी कंपनियाँ बाज़ार पर हावी हैं, जिससे नए प्रवेशकों के लिये बहुत कम अवसर मलिते हैं।
 - यह तीव्र प्रतिस्पर्द्धा नवाचार को हतोत्साहित करती है और उद्यमशीलता की विधिता को सीमित करती है।
- साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी चित्ताएँ: संवेदनशील उपभोक्ता डेटा के साथ काम करने वाले स्टार्टअप, विशेष रूप से फनिटेक और स्वास्थ्य-तकनीक में, डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
 - अकेले वर्ष 2023 में, भारत में 79 मलियन से अधिक साइबर अटैक हुए, जो वर्ष 2022 की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जिससे स्टार्टअप्स के लिये स्थायित्व एवं वित्तीय जोखिम बढ़ गया है।
 - यद्यपि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम- 2023 का उद्देश्य इन चित्ताओं को दूर करना है, लेकिन इसके प्रावधानों का अनुपालन छोटे स्टार्टअप्स के लिये संसाधन-गहन हो सकता है।

Key Government's Startup Initiatives



भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- नियमित कार्यदांचे को सरल बनाना:** सरकार को स्टार्टअप्स के लिये प्रशासनिक बाधाओं को कम करने के लियकंपनी पंजीकरण, कर फाइलिंग और अनुपालन मानदंडों जैसी नियमित प्रक्रयाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिये।
 - राष्ट्रीय एकल खड़की प्रणाली (NSWS) जैसी पहलों को सभी राज्यों तक विस्तारित करने से समाशोधन और अनुमोदन के लिये एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध हो सकता है।
 - एंजल टैक्स जैसी काराधान नीतियों के बारे में अस्पष्टता को दूर करने से अधिक घरेलू और विदेशी निविश को बढ़ावा मिलेगा।
 - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसी योजनाओं के तहत शक्तियां निविश तंत्र को सुदृढ़ करने से स्टार्टअप्स के लिये सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सकता है।
- प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण तक अभियान को बेहतर करना:** वित्तपोषण संबंधी अंतराल को दूर करने के लिये, सरकार को **स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स (FFS)** जैसी पहलों का विस्तार करना चाहिये और नजीबी निविशकों के साथ सह-निविश मॉडल पेश करना चाहिये।
 - इक्विटी फंड जुटाने में चुनौतियों का सामना करने वाले स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये SIDBI के तहत एक समर्पति उद्यम ऋण निधि स्थापति की जा सकती है।
 - अद्यतन कानूनी कार्यदांचे के माध्यम से क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे वैकल्पिक वित्तपोषण तरीकों को बढ़ावा देने से भी छोटे निविशकों को आकर्षण किया जा सकता है।
 - स्टार्टअप्स के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS)** जैसी क्रेडिट गारंटी योजनाओं को मज़बूत करने से स्टार्टअप्स को संपारशकिं-मुक्त ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना:** अनुकूलति वित्तीय प्रोत्साहन और मार्गदरशन कार्यक्रम अधिक महिलाओं को स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रवेश करने के लिये सशक्त बनाया जा सकता है।
 - NITI आयोग के तहत **महिला उद्यमिता मंच (WEP)** के दायरे का विस्तार करके इसमें क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण और बाजार संपर्क को शामिल करने से समावेशित को बढ़ावा मिल सकता है।
 - स्टार्टअप इंडिया** के तहत **महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप** के लिये समर्पति फंड शुरू करने से वित्तपोषण में लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है।
 - ओडिशा में मशिन शक्ति जैसी राज्य स्तरीय पहलों में महिला उद्यमियों के लिये समर्थन को एकीकृत करने से क्षेत्रीय पहुँच सुनिश्चित होगी।
- उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मज़बूत संबंध स्थापित करने से अनुसंधान-संचालित उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है।
 - नवाचारों के विकास और उपयोग के लिये राष्ट्रीय पहल (NIDHI)** जैसी पहलों का विस्तार करके विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में इनकायूबेशन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
 - IIT, IIM और अन्य प्रमुख संस्थानों को उद्योग-केंद्रित नवाचार प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने से शैक्षणिक अनुसंधान एवं बाजार की मांग के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकता है।
 - अटल इनोवेशन मशिन (AIM)** जैसी सरकारी योजनाओं के साथ शैक्षणिक जगत को जोड़ने से ज्ञान आधारित स्टार्टअप को और भी बढ़ावा मिल सकता है।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकिंग-रिकृत करने के लिये, सरकार को छोटे शहरों में डिजिटिल और भौतिक बुनियादी अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
 - डिजिटिल इंडिया पहल** जैसे कार्यक्रमों का विस्तार और **भारतनेट** के माध्यम से हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाया जा सकेगा।
 - स्थानीय उद्योगों के साथ साझेदारी में विशेष मार्गदरशन कार्यक्रम और कार्यशालाएँ इन क्षेत्रों की उद्यमशीलता कृष्णता का लाभ उठा सकती हैं।

- बाज़ार अभिगम और स्केलेबलिटी को सुवधिजनक बनाना: स्टारटअप्स को घरेलू और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करना उनकी स्केलेबलिटी के लिये आवश्यक है।
 - **ONDC** (डिजिटिल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क) जैसे प्लेटफॉर्मों को सुदृढ़ करने से छोटे स्टारटअप को व्यापक आपूरत शृंखलाओं और ई-कॉमर्स नेटवर्क में एकीकृत किया जा सकता है।
 - **बैंपयिन सेवा क्षेत्र योजना (CSSS)** के तहत स्टारटअप एक्सपोर्ट हब स्थापित करने से स्टारटअप को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश करने में मदद मिल सकती है।
 - सरकारी खरीद नीतियों में स्टारटअप्स के लिये एक नियमित प्रतशित अनुबंधों को अनविार्य किया जाना चाहयि, जैसा कि **सिरकारी ई-मारकेटप्लेस (GEM)** पोर्टल के माध्यम से किया गया है।
- कौशल और प्रतभित्व विकास में सुधार: स्टारटअप्स को AI, ब्लॉकचेन और IoT जैसी उभरती हुई तकनीकों में कौशल कार्यबल की आवश्यकता होती है। **कौशल भारत मणिन** के तहत कार्यकर्मों, जैसे कि **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 4.0)** में स्टारटअप की मांगों के लिये विशेष रूप से डिजिट न किये गए मॉड्यूल शामिल होने चाहयि।
 - स्टारटअप्स के साथ इंटरनेशनल और अपरेंटिशिप की पेशकश करने के लिये नजीब क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने से कौशल को उदयोग की ज़रूरतों के साथ संरेखित किया जा सकता है।
 - स्टारटअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी में समर्पित "स्टारटअप स्कलिंग सेंटर" स्थापित करने से उदयमयों की नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो सकती है।
- धारणीय और हरति स्टारटअप को प्रोत्साहन: हरति उदयमति को बढ़ावा देने से नवाचार को प्रोत्साहन के साथ-साथ जलवायु लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है।
 - **राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मणिन** और **हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं वनिमियाण (FAME)** के तहत स्वच्छ ऊर्जा स्टारटअप्स के लिये सबसेडी और प्रोत्साहन का वसितार करके इनके अंगीकरण को गतिमिल सकती है।
 - मेक इन इंडिया 2.0 के तहत समर्पित हरति स्टारटअप ज्ञान नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और धारणीय कृषि पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों के लिये इनकायूबेशन सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता कार्ययोगी का नियमाण: फानिटेक, हेलथ-टेक और एडटेक में संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा से नापिटने वाले स्टारटअप्स को दृढ़ साइबर सुरक्षा कार्ययोगी की आवश्यकता है।
 - **डिजिटिल वयक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** के तहत सख्त मानकों को लागू करने से स्टारटअप्स को प्रतिष्ठित एवं वित्तीय संबंधी जोखियों से बचाया जा सकता है।
 - **भारत साइबर अपराध समनवय केंद्र (I4C)** के माध्यम से सबसेडी वाले साइबर सुरक्षा साधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने से छोटे स्टारटअप्स के लिये सुरक्षा मजबूत हो सकती है।
 - **साइबर खतरों पर ज्ञान साझा करने के लिये सरकार समर्थति प्लेटफॉर्म** अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- वैश्वकि प्रतिस्पर्द्धधात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना: वैश्वकि प्रतिस्पर्द्धधात्मकता को बढ़ावा देने के लिये, स्टारटअप्स को अग्रणी प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहयि।
 - **इंडियाAI मणिन** जैसे कार्यकर्मों को गतिदेने से AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अधिक स्टारटअप काम कर सकेंगे।
 - **भारत-इज़रायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार नियम (I4F)** जैसी योजनाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को समर्थन देकर भारतीय स्टारटअप को वैश्वकि मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत किया जा सकता है।
 - **स्टारटअप इंडिया** के तहत सीमा पार स्टारटअप शिखिर सम्मेलनों और विनियमिय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से भारतीय स्टारटअप्स को वैश्वकि सरवोत्तम प्रथाओं से सीखने में मदद मिलेगी।
- एग्रीटेक स्टारटअप्स के लिये समर्थन का वसितार: भारत की कृषि प्रधान अरथव्यवस्था को देखते हुए, एग्रीटेक स्टारटअप्स परशिद्ध कृषि और आपूरत शृंखला डिजिटिलीकरण जैसे नवाचारों के माध्यम से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं।
 - **कृषि अवसंरचना कोष (AIF)** के अंतर्गत कार्यक्रमों का वसितार करने से कृषि प्रौद्योगिकी नवाचारों के लिये कम लागत पर वित्तीय उपलब्ध हो सकता है।
 - **PM-KUSUM** जैसी पहलों को सौर ऊर्जा चालति सचिवाई समाधान पर काम करने वाले स्टारटअप्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
 - राज्य सतर्गीय कार्यक्रम, जैसे कि महाराष्ट्र की एग्रीटेक नीति, क्षेत्र-विशिष्ट एग्रीटेक नवाचारों को बढ़ावा देने के लिये मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं।
- मैटरशपि और इकोसासिटम नेटवर्कगि को सुदृढ़ करना: वित्तीय उपलब्धि, संचालन और स्केलिंग चुनौतियों के माध्यम से स्टारटअप्स को मार्गदर्शन देने में मैटरशपि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
 - **स्टारटअप इंडिया हब** जैसे कार्यक्रमों के तहत मैटरशपि नेटवर्क का वसितार करने से स्टारटअप्स को उदयोग विशेषज्ञों एवं नवीशकों तक अभिगम प्रदान किया जा सकता है।
 - **क्षेत्रीय स्टारटअप शिखिर सम्मेलन** आयोजित करने के लिये **NASSCOM** जैसे उदयोग संघों के साथ साझेदारी करने से नेटवर्कगि के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

निषिकरण:

यद्यपि भारत की स्टारटअप इंडिया पहल ने एक समृद्ध स्टारटअप इकोसासिटम को प्रोत्साहन के साथ नवाचार और रोजगार सृजन को विशेषकर फनिटेक और हेलथटेक जैसे क्षेत्रों में वैश्वकि अग्रणीयों के रूप में स्थान दिलाया है। फरि भी स्टारटअप इकोसासिटम की प्रगतिबिनाए रखने के लिये, विनियमियक बाधाओं, फंडिंग की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान और उदयोग-अकादमिक सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है। इन क्षेत्रों को सुदृढ़ करने से स्टारटअप की संवहनीयता सुनियमित होगी, समावेशी विकास में योगदान मिलेगा और प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों (SDG) जैसे कि उत्कृष्ट श्रम (SDG 8) और उदयोग नवाचार (SDG 9) को समर्थन प्राप्त होगा, जिससे दीर्घकालिक आरथकि प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

प्रश्नोत्तरी प्रश्नोत्तरी प्रश्नोत्तरी:

प्रश्न. भारत में स्टार्टअप, विकास और नवाचार के प्रमुख चालक हैं। उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालयि और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न

प्रश्न. उद्यम पूँजी का क्या अर्थ है? (2014)

- (a) उद्योगों को प्रदान की गई अलपकालकि पूँजी
- (b) नए उद्यमियों को प्रदान की गई दीरघकालकि स्टार्ट-अप पूँजी
- (c) घाटे के समय उद्योगों को उपलब्ध कराई गई धनराशि
- (d) उद्योगों के प्रत्यक्षिप्तापन और नवीकरण के लिये धन उपलब्ध कराया गया

उत्तर: (b)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/revitalizing-startups-for-a-resilient-india>

